

03 मुझे पूरा भरोसा, दिल्ली एक बार फिर झाड़ू को ही चुनेगी- केजरीवाल

06 कुंभ देखो और कुंभ के अजूबे भी देखो

08 उत्कृष्ट ओडिशा कार्यक्रम कल से शुरू होगा, मोदी भी भाग लेंगे

दिल्ली परिवहन आयुक्त जनता की सुरक्षा से ज्यादा वाहन निर्माताओं और डीलरों के हितैषी

संजय बाटला

नई दिल्ली। जी हां यह आक्षेप हम बिना वजह नहीं लगा रहे हैं इसके पीछे कई तथ्य उपलब्ध हैं। मोटर वाहन नियम के बाहर जाकर

1. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति
2. ई रिक्शा चालकों के लिए नए लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य 10 दिन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए उपलब्ध आनलाइन प्रक्रिया को बंद करवा कर हस्तचालित प्रक्रिया का प्रयोग करवा कर लाइसेंस बनवाने

3. वाहन डीलरों द्वारा एपीमेंट की शर्तों की अवहेलना के बावजूद वाहनों के पंजीकरण और आर.सी. प्रिंट की इजाजत देना

4. वाहनों के लिए जांच की क्षमता ना होने के बावजूद निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से क्षमता से कई गुणा वाहनों की जांच के आदेश देकर वाहन मालिकों को परेशानी में डालना इत्यादि अनेक आदेश उपलब्ध हैं जो यह सिद्ध करते हैं की परिवहन आयुक्त के लिए दिल्ली की जनता की सुरक्षा से अधिक दिल्ली परिवहन विभाग से स्टेट अप्रूवल के साथ ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त पंजीकृत वाहन निर्माताओं और डीलरों के हितैषी हैं।

1. दिल्ली में जनता की जगह निर्माताओं और डीलरों के काम बिना रुकावट होते रहे के उद्देश्य से तकनीकी अधिकारियों जिन्हें तकनीकी जानकारी है के स्थान पर गैर तकनीकी अधिकारियों जिन्हें वाहन के प्रति जरा सी भी जानकारी नहीं है और राजस्व में इजाफा की पूर्ण तकनीक रखते हैं को जानबूझ कर नियमों और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर के नियुक्त कर दिया।

2. दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य 10 दिन की ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जो ई रिक्शा चालक को ट्रेनिंग

देने वालों द्वारा आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य किया हुआ था को ई रिक्शा निर्माताओं और डीलरों के हितैषी में हस्तचालित जिसकी जांच संभव नहीं को इजाजत दे दी। ई रिक्शा चालक रिक्शा चलाने के लिए अगर शिक्षित नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ई रिक्शा चला रहा है तो उसका हर्जाना चुकाएगी दिल्ली की जनता।

3. दिल्ली में वाहन बेचने वाले डीलरों को वाहन पंजीकरण कर वाहन की आर.सी. प्रदान करने के लिए एपीमेंट के अनुसार दी गई इजाजत में वाहन डीलर को परिवहन विभाग में बैंक गारंटी जमा करवानी अनिवार्य है और बैंक गारंटी समाप्त होने के साथ ही एपीमेंट के अनुसार डीलर को दी गई इजाजत समाप्त हो जाती है पर परिवहन आयुक्त की वाहन डीलरों के हितैषी होने के कारण वाहन डीलर की बैंक गारंटी जमा नहीं होने पर भी वाहन पंजीकरण और आर.सी. प्रिंट करने की अनुमति दी जा रही है जो जनता के साथ कभी भी धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।

4. दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा लगाई गई मशीनों की क्षमता ना होने के बावजूद वाहनों को उसी से जांच करवाकर जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिससे वाहन मालिकों को जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट ही उपलब्ध नहीं हो पा रही और उसका फायदा उठा रहे हैं वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट दिलवाने वाले और निजी कंपनी।

अब आप ही बताएं की जनता की सुरक्षा के लिए उपलब्ध आईएसएस अधिकारी ही अगर जनता की सुरक्षा की जगह निजी कंपनी, वाहन निर्माताओं, वाहन डीलरों और राजस्व इजाफा में लिये जाते तो जनता को सुरक्षा मुहैया कौन करवाएगा ?

Request for an urgent appointment

Add label



Parivahan Vishesh 10:54 PM
to pstolg.delhi, csdelhi, as...

From Parivahan Vishesh · parivahanvishesh@gmail.com

To pstolg.delhi@nic.in
csdelhi@nic.in
as-teansport-morth@gov.in

Cc commtpt@gmail.com

Date Jan 27, 2025, 10:54 PM

View security details

Honourable Sir,

दिल्ली परिवहन आयुक्त जनता की सुरक्षा से ज्यादा वाहन निर्माताओं और डीलरों के हितैषी

जी हां यह आक्षेप हम बिना वजह नहीं लगा रहे हैं इसके पीछे कई तथ्य उपलब्ध हैं। मोटर वाहन नियम के बाहर जाकर

1. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति
2. ई रिक्शा चालकों के लिए नए लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य 10 दिन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए उपलब्ध आनलाइन प्रक्रिया को बंद करवा कर हस्तचालित प्रक्रिया का प्रयोग करवा कर लाइसेंस बनवाने
3. वाहन डीलरों द्वारा एपीमेंट की शर्तों की अवहेलना के बावजूद वाहनों के पंजीकरण और आर.सी. प्रिंट की इजाजत देना
4. वाहनों के लिए जांच की क्षमता ना होने के बावजूद निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से क्षमता से कई गुणा वाहनों की जांच के आदेश देकर वाहन मालिकों को परेशानी में डालना इत्यादि अनेक आदेश उपलब्ध हैं *जो यह सिद्ध करते हैं की परिवहन आयुक्त के लिए दिल्ली की जनता की सुरक्षा से अधिक दिल्ली परिवहन विभाग से स्टेट अप्रूवल के साथ ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त पंजीकृत वाहन निर्माताओं और डीलरों के हितैषी हैं*

मौनी अमावस्या पर 1000 अतिरिक्त बसों का होगा संचालन यात्रियों के लिए कंबल और चाय की भी होगी व्यवस्था



यूपी में मौनी अमावस्या पर एक हजार अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 29 जनवरी को होने वाले शाही स्नान में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। परिवहन विभाग द्वारा मौनी अमावस्या पर्व पर 1000 अतिरिक्त बसें चलाएगा, ताकि महाकुंभ स्नान के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। परिवहन निगम ने मौनी अमावस्या पर 1000 बसों के संचालन की योजना पहले से ही की थी। मौनी अमावस्या पर आने वाले काफी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 अतिरिक्त बसों के संचालन

के निर्देश दिए हैं।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने शनिवार को योजना भवन में 29 जनवरी व तीन फरवरी को पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्नान को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आएंगे। पुलिस व प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विभागीय अधिकारी श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराएंगे। प्राइवेट ऑपरटर्स से भी संपर्क किया जाए की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रयागराज में बने नौ अस्थाई

बस स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने, कंबल, चाय आदि की व्यवस्था के लिए भी एनजीओ आदि से संपर्क करें। यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं बस स्टेशनों पर मुहैया कराई जाएं। जिनके रहने की व्यवस्था नहीं हो उन्हें अस्थाई बस स्टेशनों पर भी रुकने की व्यवस्था करें। अस्थाई बस स्टेशनों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक प्लान तैयार करें।

परिवहन मंत्री ने बसों में फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी डिवाइस की व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एंबुलेंस व व्हेन की व्यवस्था भी समुचित करने को कहा। ताकि आपातकाल में तत्काल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। बैंक में सभी जिलों के प्रशासनिक, पुलिस विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे।

ड्राइवर द्वारा कंडक्टर के बिना जनता को गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाने के लिए दौड़ाई रूट पर बस

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्राप्त सूचना के अनुसार 26 जनवरी को बस बिना कंडक्टर के करीब 7 किलो मीटर तक रूट पर दौड़ी, सभी यात्रियों ने बिना टिकट के ही करी यात्रा। घटना शाम 5.47 की है मोती नगर के ड्राइवर को कंट्रोल रूम से सूचना आने पर पता चला कि बस में कंडक्टर नहीं है। रूट नंबर 778, बस नंबर DL51EV 4173, शाम को अपने गणतंत्र स्थान इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से शाम 4.30. बजे पर चलने का था। टर्मिनल पर ड्यूटी दे रहे कंडक्टर ने बस को समय देख कर बस चलवा दी। बस में कई सवारियां अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बैठी हुई थीं। बस में कंडक्टर की उपस्थिति नहीं होने के कारण बस में बैठी सवारियां टिकट को लेकर असमंजस में थे को बस में कंडक्टर ही नहीं है तो टिकट कौन देगा। अचंचे की बात यह थी की तब भी बस के ड्राइवर को पता नहीं चला की बस में कंडक्टर उपलब्ध नहीं है, मोती नगर



आकर ड्राइवर को सवारियों से पता चला की बस में कंडक्टर ही नहीं है। कंडक्टर ने कंट्रोल नंबर पर सूचना दे कर बताया की बस ड्राइवर बिना कंडक्टर को लिए ही बस को चला कर ले गया है। कंट्रोल रूम में ड्राइवर

को सूचना दी तब जाकर ड्राइवर ने मोती नगर बस रोकी और कंडक्टर का इंतजार किया। कुछ देर बाद कंडक्टर ने बस में अपनी सीट संभाली और जल्दी जल्दी सभी सवारियों को टिकट दी।

17 अप्रैल से शुरू हो सकती हैं उड़ानें; जानें क्या-क्या बनकर हुआ तैयार, कहां अभी भी चल रहा काम

परिवहन विशेष न्यूज

हवाई अड्डे से 17 अप्रैल को उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है। हवाई अड्डे के दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर पर विकसित किए जाने वाले एमआरओ हब और रनवे के संबंध में भी प्रगति हुई है।

नोएडा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का 78 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भवन का फर्श तैयार हुआ है एस्कलेटर और बैगज डिलीवरी के लिए जरूरी उपकरण लगा दिए गए हैं। बिल्डिंग को छत का निर्माण कार्य चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग से रनवे तक सफर को पूरा करने के लिए टैक्सो-वे, सड़क सहित अन्य कार्य भी करीब 89 फीसदी पूरे हो गए हैं। टर्मिनल भवन तैयार हो जाने के बाद 10 एयरोब्रिज बनाए जाएंगे।

हाल ही में नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक ईशान प्रताप सिंह ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। इसी दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में निर्माण कार्य का पूरा ब्योरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, टर्मिनल बिल्डिंग और एयर साइट का विकास तेजी से जारी है। सड़कें, पार्किंग सुविधाएं और सार्वजनिक परिवहन कनेक्शन की भौतिक प्रगति 78.7 फीसदी है। एयरसाइट के रनवे, टैक्सोवे, एप्रन और नेविगेशन सिस्टम का 88.9 फीसदी काम



पूरा हो चुका है। वित्तीय तौर पर भी हवाई अड्डे के पहले चरण में 90 फीसदी प्रगति हासिल की है। कुल स्वीकृत बजट 10,056 करोड़ रुपये में से 9,024 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसमें 1,334 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आवंटित 4,326 करोड़ रुपये और ज्यूरिख एजी की सहायक कंपनी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) द्वारा परियोजना विकास के लिए निर्धारित 5,730 करोड़ रुपये

शामिल हैं।

अहम है कि हवाई अड्डे से 17 अप्रैल को उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है। हवाई अड्डे के दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर पर विकसित किए जाने वाले एमआरओ हब और रनवे के संबंध में भी प्रगति हुई है। एमआरओ हब की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निविदा दस्तावेज तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी है।

एटीसी टावर का निर्माण पूरा, एएआई ने शुरू की निगरानी

एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण भी पूरा हो गया है। इसके रूपास का काम पूरा होने के बाद अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की निगरानी में हवाई यातायात प्रबंधन के परिचालन प्रणाली की जांच जारी है। कार्यदायी संस्था यापल की ओर से बोते दिसंबर में सफल सत्यापन उड़ान के बाद एयरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। मार्च तक इस लाइसेंस के मिलने की उम्मीद है।

हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर इंटरचेंज का काम जारी

यमुना एक्सप्रेसवे को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली आठ-लेन इंटरचेंज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार को उसके टर्मिनल भवन से जोड़ने वाले हिस्से का निर्माण अब अंतिम चरण में है। करीब 31 किमी लंबी सड़क बल्लभगढ़ में एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इसी सड़क को यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से जोड़ा गया है।

एयरपोर्ट के पहले चरण के 10 हजार करोड़ रुपये के बजट का 90 फीसदी उपयोग किया जा चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग से रनवे तक सफर को पूरा करने के लिए टैक्सोवे, सड़क सहित एयर साइट के अन्य कामों को भी 89 फीसदी पूरा कर लिया गया है।

थर्ड पार्टी बीमा नहीं है? तो आपको ईंधन या फास्टेग नहीं मिलेगा, जल्द ही आने वाले हैं नए नियम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के मकसद से उपायों पर विचार करने का निर्देश दिया है। इन उपायों में बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन भरने या फास्टेग लेन का इस्तेमाल करने से रोकना शामिल है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के मकसद से उपायों पर विचार करने का निर्देश दिया है। इन उपायों में बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन भरने या फास्टेग लेन का इस्तेमाल करने से रोकना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि बिना बीमा वाले वाहन मालिकों के

ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल (नवीनीकरण) नहीं किया जाएगा।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। इस तरह का बीमा दुर्घटना में किसी थर्ड पार्टी (तीसरे पक्ष) को हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करता है। हालांकि, कानूनी जरूरत के बावजूद, भारतीय सड़कों पर आधे से ज्यादा वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना एक अपराध है, जिसके लिए पहली बार अपराध करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना, तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। बार-बार अपराध करने पर जुर्माना बढ़कर 4,000 रुपये हो जाता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय जल्द

ही वाहन सेवा नियमों में बदलाव करने के लिए प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है। जिसमें वाहन से संबंधित सेवाओं को बीमा कवरेज के प्रमाण के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन नए नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए उपायों का प्रस्ताव दिया है। जिसमें बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन भरने और फास्टेग लेन का इस्तेमाल करने से रोकना शामिल है। साथ ही वाहन सेवाओं को बीमा कवरेज से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है।

इसी के अनुरूप, संसदीय स्थायी समिति ने थर्ड पार्टी बीमा कवरेज को बढ़ाने के संबंध में

सरकार को सिफारिशें पेश की हैं। समिति ने वाहन पंजीकरण और बीमा स्थिति को व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डेटा एकीकरण, ई-चालान और अलग-अलग राज्यों को डेटा रिपोर्टिंग बढ़ाने की भी वकालत की है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, 2024 में भारतीय सड़कों पर चलने वाले अनुमानित 35-40 करोड़ वाहनों में से सिर्फ 50 प्रतिशत ही थर्ड-पार्टी बीमा द्वारा कवर किए गए हैं।

इसके अलावा, बीमा सत्यापन को FASAg (फास्टेग) और अन्य डिजिटल सेवाओं से जोड़ने से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जिससे यह ज्यादा कुशल और प्रभावी बन सकता है।



मुझे पूरा भरोसा, दिल्ली एक बार फिर झाड़ू को ही चुनेगी- केजरीवाल

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली की जनता को केजरीवाल की गारंटी है। दिल्ली की जनता से हमारा रिश्ता चांदों का नहीं, बल्कि गारंटी का है। यह केजरीवाल की गारंटी है। जो कहा है, वो करके दिखाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से झाड़ू को ही चुनेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, महिला सम्मान, संजीवनी व पुजारी-ग्रंथी योजना, पानी के गलत बिल माफ, डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप, छात्रों की फ्री बस यात्रा व मेट्रो के किराए में 50 फीसद की रियायत समेत 15 गारंटी हम अगले पांच साल में पूरा करेंगे। साथ ही, पहले से मिल रही मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा जारी रहेगी। 'आप' की सरकार में हर परिवार को 25 हजार रुपए महीना फायदा हो रहा है। अगर कमल का बटन दब गया तो इतना अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सीएम आतिशी, सांसद राजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल संजय भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि आज हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 'केजरीवाल की गारंटी' जारी कर रहे हैं। 'केजरीवाल की गारंटी' का मतलब पक्की बात है। इसमें कभी बात कुछ भी नहीं होती है। जिस तरह ये लोग कभी संकल्प पत्र कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। सबको पता है कि इनके

संकल्प पत्र फर्जी होते हैं। जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा। इसके एक-डेढ़ साल बाद अमित शाह से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि वह चुनावी जुमला था।

रोजगार की गारंटी
महिला सम्मान योजना
सरकार बनने के बाद हर महीने हर महिला के खाते में 2100 रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसे जल्द से जल्द और सबसे पहले लागू करेंगे।

संजीवनी योजना
60 साल से उपर उम्र होने के बाद हमारे बुजुर्गों को चिंता सताने लगती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा? कहाँ इलाज कराएंगे, कहाँ इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं सभी बुजुर्गों को आशवासन देना चाहता हूँ कि आपका यह बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। चाहे मुझे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़े या प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े। उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी।

पानी के गलत बिल माफ की गारंटी
24 घंटे साफ पानी, यमुना की सफाई और यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़क बनाने की गारंटी।

डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में इतने गरीब होने के बावजूद पीएचडी करके आए



थे। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तब उनके पास पैसे खत्म हो गया। उन्हें पढ़ाई छोड़कर घर वापस आना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पैसे का इंतजाम किया और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस गए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी दलित समाज के बच्चे का सपना पैसा नहीं होने के कारण पूरा न हो। डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। उसके आने-जाने, रहने, खाने समेत सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी।

छात्रों को गारंटी
महिलाओं की तरह ही आम आदमी पार्टी की सरकार छात्रों को भी दिल्ली सरकार की बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त करेगी और मेट्रो के किराए में 50 फीसद की रियायत दी जाएगी।

पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना
किराएदारों को फ्री बिजली-पानी*
दिल्ली में हमने बिजली और पानी के बिल ज़ीरो कर दिए। लेकिन कई किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिले।

सीवर की समस्या होगी दूर
दिल्ली में कई जगह सीवर की समस्या है। कई जगह सीवर चोक हैं। जब मैं जेल में था। इन्होंने कई जगह सीवर में सीमेंट के कट्टे और बोल्ट डाल दिए। ताकि जनता को तकलीफ हो और जनता केजरीवाल से नाराज हो जाए। इन्होंने वोट लेने के लिए दिल्ली की जनता को परेशान करने में कोई रणनीति नहीं छोड़ी। अब जहां-जहां सीवर ब्लॉक हैं और ओवर फ्लो कर रहे हैं, उसे हम सरकार बनने के बाद 15 दिन में ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो सीवर की लाइनें खर्चा दिल्ली सरकार देगी।

राशन कार्ड की गारंटी
कई साल से नए राशन कार्ड नहीं बने हैं। गरीबों को फ्री राशन का फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार बनने के बाद नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके। अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें।

ऑटो वालों को गारंटी
ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा वाले भाइयों को बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। उनको 10 लाख रुपए का लाइफ और 5

लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
आरडब्ल्यू को गारंटी
दिल्ली के अंदर कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भाजपा की केंद्र सरकार की थी। लेकिन आज दिल्ली की कानून-व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची है। लोग डर के भय में जी रहे हैं।

हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, वो किया। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं। इस दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की सभी आरडब्ल्यू को प्राइवेट सिम्युरिटी गार्ड रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा।

*भाजपा ने एलान कर दिया है कि उसकी सरकार बनी तो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लीनिंग, महिलाओं की बस यात्रा बंद कर देगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो 25 हज़ार रुपए एक-एक परिवार के उपर अतिरिक्त खर्चा हर महीने आने लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि हर गरीब परिवार 25 हज़ार रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए सक्षम है। मुझे लगता है कि कई गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। यहीं मिडिल क्लास, जिसकी 80 हजार से 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, उसके लिए भी 25 हज़ार रुपए का अतिरिक्त बोझ कोई छोटा बोझ नहीं है। वह भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दिल्ली में लंबे-लंबे पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। झाड़ू को हम घर की लक्ष्मी बनाते हैं। अगर आप झाड़ू का बटन दबाते हैं तो सीधे-सीधे आपको 25 हज़ार रुपए महीने का फायदा हो रहा है।

वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने महिला सम्मान योजना लागू होने में 'सिर्फ आठ दिन और' का काउंटाउन को खोला

मुख्य संवाददाता सुष्मा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी पर सोमवार को डबल मोहर लग गई। यह मोहर खुद 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना हस्ताक्षर करके लगाई। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आने का काउंटाउन शुरू हो गया है। पार्टी का मेनिफेस्टो जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना को लेकर अलग से गारंटी पत्र जारी किया और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल यह गारंटी देता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों के लिए महिला सम्मान राशि योजना शुरू करूंगा।

इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने महिला सम्मान योजना लागू होने में 'सिर्फ आठ दिन और' का काउंटाउन खोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल की 15 गारंटी है। इसमें चुनाव के बाद

महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति महीने की गारंटी पर काम शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद लिख कर-साइन कर के गारंटी दी। केजरीवाल की गारंटीयों से दिल्ली के हर परिवार को कम से कम 25,000 की बचत होगी।

वहीं, वरिष्ठ नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कीचड़ में कमल खिलता है और झाड़ू से कीचड़ साफ होता है। इसलिए झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 25 हजार रुपए हर महीने बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जब गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया तो गारंटी शब्द चुरा लिया गया। अब जो अरविंद केजरीवाल ने गारंटी पर गारंटी देने का काम किया है, इसे भी साल भर में दूसरी पार्टियां चुरा लेंगी। दिल्ली चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हैं। पांच फरवरी को मतदान होना है। महिलाओं को 2100 रुपए मिलने का समय भी अब दूर नहीं है। अब काउंटाउन शुरू हो गया है। महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है कि ये सात-आठ दिन जल्द से जल्द पूरे हों और उनको 2100 रुपए मिलने चालू हों।

रोहिणी में कार्यालय उद्घाटन से पहले हवन व पूजा का हुआ आयोजन



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है गुजरात स्थित धोलेरा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इसी धोलेरा स्मार्ट सिटी पर काम कर रही ब्रोचर रिजलिटी के दिल्ली कार्यालय का शनिवार को रोहिणी में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के गुजरात इकाई के प्रमुख भी उपस्थित हुए।

भाजपा के तमाम दुष्प्रचार के बाद भी दिल्ली में आ रही है आप: मोहम्मद जियाउल्लाह

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली उर्दू अकादमी के गवर्निंग काउंसिल मेंबर मो. जियाउल्लाह ने कहा कि उर्दू भारत की दूसरी जुवान के साथ-साथ आम बोलचाल की भी भाषा है, परंतु इसको सशक्त बनाने के लिए सरकार भरपूर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से इसका गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि इस जुवान को किसी खास संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मोहम्मद जियाउल्लाह ने कहा कि सीबीएसई में उर्दू जुवान को खत्म कर दिया गया जबकि इस जुवान में भी छात्र तालीम लेते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उर्दू जुवान के संवर्धन के लिए काफी काम किया है, परंतु केंद्र एवं कई राज्यों की सरकारों इसे तरजीह नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू जुवान के टाइपिस्ट, ट्रांसलेटर आदि के काफी पद खाली हैं। इन पदों को भरा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी मोहम्मद जियाउल्लाह अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप सुप्रियो अरविंद केजरीवाल के विजन, कार्यशाला से दिल्ली का काफी विकास हुआ है तथा जनता को कई तरह की राहते मिली है। सभी के लिए सहज सुलभ शिक्षा हेतु 25% बजट आप सरकार प्रदान कर रही है। वही हाथ पर एकेडमिक के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली की सरकारी स्कूलों के 300 छात्रों ने आईआईटी, जेई में सफलता प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर काम कर रही है, वहीं मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा, राशन की पर्याप्त व्यवस्था, स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर अंकुश आदि ऐसे काम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का और तेजी से विकास हो सकता था, परंतु केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वहीं उपराज्यपाल के माध्यम से विभिन्न तरह के विकास में रुकावट डालकर विकास कार्यों को बाधित किया गया। दिल्ली की प्रबुद्ध जनता इन तमाम विषयों को जान रही है। यही कारण है कि 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को मतदान कर फिर से दिल्ली में आप की सरकार बनाएगी।

मकसद है दिल्ली के लोगों को सही और सटीक प्रोपर्टी बिना किसी ठगी के उपलब्ध कराना या सके। आज जिस तरह से लोगों के साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है तो ऐसे समय में लोगों को रोजाना की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। उपस्थित लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि दिल्ली में कंपनी का ऑफिस होने से अहम दिल्ली बैठे धोलेरा में इन्वेस्ट किया जा सकेगा।

वरिष्ठ फोटो पत्रकार एम. रामिश के निधन पर हज मंजिल में शोक सभा का आयोजन

नई दिल्ली (मुख्य संवाददाता सुष्मा रानी)

वरिष्ठ फोटो पत्रकार एम. रामिश के आकस्मिक निधन पर वकिंग जर्नलिस्ट क्लब की ओर से हज मंजिल में शोक सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी स्टाफ वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि एम. रामिश की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम सब अल्लाह के फैसले का सामना करने को मजबूर हैं। हम भी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मौत की खबर सुनकर उन्हें सदमा लगा, क्योंकि हज कमेटी में अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। वह एक सुश्रुतिजाज और जिंदादिल इंसान थे। सामाजिक कार्यकर्ता सईद खान ने बताया कि एम. रामिश के साथ उनका रिश्ता 1991 से था। हम दोनों जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू से ही वे अपने हंसमुख स्वभाव और अपनी बात खुलकर कहने के लिए जाने जाते थे। उनसे जुड़ी हमारी कई यादें हैं। 1991 के समय में रामिश हमारे शिक्षक थे वह एक मित्र था, और हमने उसे 2025 में भी इसी तरह पाया।

डॉ. नफीस कुरैशी ने बताया कि एम. रामिश की नजीबाबाद में जमीनी थी, जिसे कुछ लोगों ने फर्जी आवेदन बनाकर बेच दिया। इस सिलसिले में उन्हें नजीबाबाद जाना पड़ता था। मरे कुछ रिश्तेदार नजीबाबाद से हैं, इसलिए रामिश ने मुझे भी इस बारे में बात की थी। मैं



सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस जमीन को वापस दिलाने में मदद करें। कुछ करें, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पास रख लिया था। के बच्चों को अगर यह जमीन मिल जाती है तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। एडवोकेट रईस अहमद ने बताया कि रामिश की मौत के समय वह दिल्ली से बाहर थे। मैं उनसे अक्सर फोन पर बात करता था। वह अपने काम के प्रति बहुत गंभीर व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद, मैंने वकिंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के दिशा-निर्देश प्रकाशित किए और उन्हें कई पत्रकारों के साथ साक्षा किया। इसका उद्देश्य यह है कि यदि डीआईपी, पीआईबी या सिर्फ कामकाजी पत्रकारों में से किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को सरकार से पांच लाख रुपये का

मुआवजा मिल सकता है। इस संबंध में हम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हैं यदि जरूरत हो तो। प्रसिद्ध कवि इकबाल फिरदौसी ने एम. रामिश को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वकिंग जर्नलिस्ट्स क्लब के अध्यक्ष फारजान कुरैशी ने कहा कि क्लब की स्थापना पत्रकारों के साथ दुश्मनी होने पर उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष एफआई इस्माइली, क्राइम रिपोर्टर अमीर अहमद राजा, मनोज टंडन, हाजी रियाज उद्दीन, सादिक शेरवानी, जमील अंजुम देहलवी, एडवोकेट असलम अहमद, मुहम्मद मुस्तकीम खान, जावेद रहमान, मुहम्मद ओवेस आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। एम. रामिश के

साथ उनके रिश्ते के बारे में बताया। एम. रामिश के तीन भाई और दो बेटे भी शोक सभा में शामिल हुए। अंत में, मस्जिद एंजली-अरबी स्कूल के इमाम और खतीब मौलाना मुहम्मद कासिम कासमी ने सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व किया। महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में दिल्ली राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशफाक अहमद आरिफी, उप कार्यकारी अधिकारी मोहिम्म अली, मुहम्मद नईम मलिक, नईम अंसारी, शमसुद्दीन, शफी देहलवी, डॉ. सगीर अख्तर, मुहम्मद शमीम, असद मियां, नवाबुद्दीन, इरफान अहमद, एम शामिल हैं। नफीस, गुलजार अहमद और शाहिद गंगोही के नाम उल्लेखनीय हैं। युवा पत्रकार सैयद आदिन अली हक ने बैठक का संचालन किया।

सांसद राघव चड्ढा ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी प्रदीप मित्तल के समर्थन में किया शानदार रोड शो

मुख्य संवाददाता सुष्मा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल के लिए एक भव्य रोड शो किया। रोड शो में रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत का भरोसा जताया।

रोड शो के दौरान, राघव चड्ढा ने क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए कहा, "जिस तरह से लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वह दिल को छू लेने वाला है।" "एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ जीतने का रही है।"

जनता का अभूतपूर्व समर्थन
रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में

रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के नागरिक मौजूद थे। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर पार्टी के समर्थन में हाथ हिलाते और 'फिर लाएंगे केजरीवाल' के नारे लगाते दिखे। सांसद राघव चड्ढा ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, "आप सभी का यह समर्थन हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाला है। आप ही हमारी ताकत हैं। इस बार भी हम आपका समर्थन और विश्वास से दिल्ली को और बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं।"

आप की उपलब्धियों का किया जिक्र

राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में AAP सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा, "हमने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी, मोहल्ला क्लीनिक के जरिए सभी को मुफ्त और



बेहतरीन इलाज दिया, और दिल्ली को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देकर हर परिवार का जीवन आसान बनाया है। यह आपकी ही पार्टी है, जो आपको जरूरतों और परेशानियों को समझती है और उन्हें हल करने का काम करती है।

युवाओं और महिलाओं के लिए खास संदेश

रोड शो में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी शामिल हुए। सांसद राघव चड्ढा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "हमारा मकसद है कि हर युवा को रोजगार मिले, हर परिवार में खुशहाली आए।" रोड शो में 'आप' के झंडे हाथों में लिए युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। इस दौरान कई युवाओं ने सांसद

रोहिणी फेडरेशन ऑफ सी.जी.एच.एस एवं अखिल रोहिणी जाट सभा ने किया कार्यक्रम का आयोजन



नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रोहिणी फेडरेशन ऑफ सी.जी.एच.एस एवं अखिल रोहिणी जाट सभा द्वारा संयुक्त रूप से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रोहिणी से भाजपा प्रत्याशी विजेन्द्र गुप्ता का शानदार स्वागत किया और आगामी चुनावों में जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं। यह कार्यक्रम सांवरिया टेट, जापानी पार्क, सैक्टर-10, रोहिणी में आयोजित किया गया जिसमें लाभार्थी एक हजार से भी अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष सहयोग के लिए विजेन्द्र गुप्ता

और अनुराग ठाकुर द्वारा ब्रोचर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से डॉ. अक्षय कुमार, श्री बांके बिहारी केंटर से जीवन अरोड़ा एवं सांवरिया टेट से अभिषेक जैन और नरेश शर्मा को डॉफी देकर सम्मानित किया गया। रोहिणी फेडरेशन ऑफ सी.जी.एच.एस से सर्वश्री ओ.पी. मलहोत्रा, आर्य मुनि, डा. एस.एल. सागर, नैपाल सिंह, प्रदीप हंस, करमवीर खत्री, हर्ष जिन्दगर, रामावतार नैय्यर, ज्योति शर्मा, नीरज ढीगरा, राजबीर राणा, विक्रम ठाकरान, राजेंद्र शर्मा, गजेंद्र यादव, सतीश सागर, संगीता शर्मा और डॉली मुत्तरेजा उपस्थित रहे। रोहिणी जाट सभा से आर्य मुनि, करमवीर खत्री, निर्मला चहल और राजेश छिल्लर उपस्थित थे।

व्यापारियों को इस बार इस बजट से काफी उम्मीद है इस बार बजट में व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए साथ ही कम ब्याज में जल्दी से जल्दी लोन मिले जिससे जिससे छोटे व्यापारी को आने वाले समय में व्यापार करने में आसानी हो। जीएसटी व इनकम टैक्स देने वाले व्यापारियों के लिए बीमा योजना की भी घोषणा हो। जीएसटी में भी सुधार किया जाना चाहिए जिसमें व्यापार करने में आसानी हो।



परमजीत सिंह पन्ना (चेयरमैन) फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन

जेएसडब्ल्यू एमजी मैजेस्टर में मिल सकते हैं ये बेहतरीन फीचर्स, इंजन भी होगा दमदार, जानें कब तक हो सकती है

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई दमदार एसयूवी को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से MG Majestor के तौर पर डी प्लस सेगमेंट में SUV को लाया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। कितना दमदार इंजन इसमें दिया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन Cars and SUVs को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान डी प्लस सेगमेंट में नई एसयूवी के तौर पर MG Majestor को पेश किया है। इस एसयूवी को कब तक लॉन्च किया जा सकता है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे लाया जा सकता है। कितना दमदार इंजन इसमें दिया जा सकता है। किस कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्द लॉन्च होगी JSW MG Majestor SUV

JSW MG की ओर से MG Majestor को डी प्लस एसयूवी सेगमेंट में जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर भारतीय बाजार में 17 से 22 जनवरी 2025 के बीच हुए Auto Expo 2025 के दौरान पेश किया गया है।

JSW MG Majestor Features
एमजी मोटर्स की ओर से Majestor में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, फ्रंट



में बड़ी ग्रिल, 20 इंच अलॉय व्हील्स, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल टोन इंटीरियर, टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलैस चार्जिंग पोर्ट, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स जैसे कई फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, बीएसडी, एलसीए, आरसीटीए, डीओडब्ल्यू, सेल्फ एडैप्टिव क्रूजिंग और ADAS जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

JSW MG Majestor Engine
कंपनी की ओर से इसे पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के विकल्प के साथ पेश किया जा सकता

है। एमजी इसमें दो लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दे सकती है। पेट्रोल इंजन से इसे 184 किलोवाट की पावर और 410 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके अलावा टर्बो डीजल इंजन से एसयूवी को 160 किलोवाट की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। दोनों ही इंजन के साथ एसयूवी में 4x4 की सुविधा को भी दिया जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ इसकी टॉप स्पीड 190 और डीजल इंजन वेरिएंट की टॉप स्पीड 175 KMPH तक हो सकती है। इसमें कंपनी की ओर से 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को दिया जा सकता है।

JSW MG Majestor Price

एमजी की ओर से अभी इस एसयूवी को भारत में सिर्फ पेश किया गया है। लेकिन लॉन्च के समय ही कीमतों की सही जानकारी मिल पाएगी। JSW MG Majestor की संभावित एक्स शोरूम कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
कैसे मिलेगी चुनौती
JSW MG की ओर से Majestor को D+ SUV सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को June-July 2025 के आस-पास भारत में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। जिसके बाद इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner Legender जैसी एसयूवी के साथ होगा।

जेएसडब्ल्यू एमजी कर रही बड़ी तैयारी, सिर्फ आई.सी.ई और ई.वी ही नहीं हाइब्रिड कारों को भी लाया जाएगा भारत



परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG ने Auto Expo 2025 के दौरान कई कारों को पेश किया है। इसके साथ ही नई तकनीक वाली कुछ कारों को शोकेस भी किया है। जिनमें से कुछ को काफी जल्द लॉन्च किया जाएगा।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG मोटर्स की ओर से 17 से 22 जनवरी 2025 के दौरान आयोजित किए गए Auto Expo 2025 में तीन Cars and SUVs को पेश किया है। इसके अलावा कंपनी ने प्रीमियम डीलरशिप JSW MG Select को भी शोकेस किया है। भविष्य की कारों के साथ ही कंपनी की रणनीति पर JSW MG के चीफ ग्रोथ अधिकारी गौरव गुप्ता ने Jagran.com ने खास बात की।

सवाल - JSW MG की ओर से जनवरी 2025 में कई वाहनों को पेश किया गया है। साथ ही JSW MG Select को भी लाया गया है। इसमें किन कारों को ऑफर किया जाएगा।

जवाब - एमजी सिलेक्ट कंपनी की लज्जती सेगमेंट वेकर है। क्योंकि भारत में लज्जती सेगमेंट की भी तेजी मांग बढ़ रही है। इसके लिए नए उत्पादों के साथ ही बेहतरीन अनुभव, नए ब्रॉन्ड, नए वाहनों की जरूरत होगी, जिसमें अच्छी कीमत वाली कारों की भी मांग रहेगी। ऐसे में JSW MG की ओर से MG Select को लाया गया है। अप्रैल 2025 से देश के 12 शहरों से इसे शुरू किया जाएगा।

सवाल - एमजी की ओर से Cyberster और M9 को पेश कर दिया गया है, इनमें किस तरह की खासियत दी गई है।

जवाब - JSW MG Select से कंपनी JSW MG Cyberster को ऑफर करेगी, जो दुनिया की सबसे तेज रोडस्टर है। यह 3.2 सेकंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जा सकती है। JSW MG Cyberster के अलावा JSW MG Select से JSW MG 9 को भी ऑफर किया जाएगा। यह एक लज्जती एमपीवी है और अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी भी है। इसमें आराम के साथ ही तीसरी सीट में काफी जगह दी गई है। सीट में मसाज सहित कुछ बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

सवाल - क्या कंपनी की प्राथमिकता EVs पर ज्यादा हो गई है और जिससे ICE सेगमेंट का पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है।

जवाब - नहीं ऐसा नहीं है। हम ईवी के साथ ICE सेगमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं और बाजार की जरूरत को देखते हुए कारों को ला रहे हैं। Auto Expo 2025 में ही ICE सेगमेंट की JSW MG Majestor को पेश किया है। अब लोगों को प्रीमियम कारें ज्यादा पसंद आ रही हैं। ऐसे में अब D सेगमेंट के साथ ही D+ सेगमेंट में भी एसयूवी को ला रहे हैं। JSW MG

Majestor से हम D+ सेगमेंट में एंटी ले रहे हैं।

सवाल - JSW MG की ओर से भारत में Windsor को लाया गया है। जिसे बेहतरीन प्रतिक्रिया भी मिल रही है। ऐसे में भविष्य में और क्या योजनाएं हैं।

जवाब - कंपनी की कुल बिक्री में 70 फीसदी योगदान NEV शामिल है। भारत में ICE सेगमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस सेगमेंट में भी मांग लगातार जारी रहेगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम EV के साथ ही ICE सेगमेंट के वाहनों को भी समय समय पर बाजार में लाते रहेंगे।

सवाल - अगले कुछ सालों में और किन कारों को भारतीय बाजार में देख सकते हैं। एक से दो सालों में और किन कारों को भारतीय बाजार में लाया जा सकता है।

जवाब - देखिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल JSW MG Cyberster, M9 और Majestor को लाने की तैयारी की जा रही है। 2025 और 2026 के लिए भी और तैयारियां की जा रही हैं। जिनमें अलग-अलग स्टाइल, ईंधन, सेगमेंट में आगे भी कारों को भारत लाया जाएगा।

सवाल - ICE और EV सेगमेंट के अलावा हाइब्रिड सेगमेंट की कारों को भी भारत में पसंद किया जाता है। कंपनी की ओर से इस सेगमेंट के लिए क्या तैयारियां हैं।

जवाब - हाइब्रिड तकनीक वाली कारों पर एमजी की ओर से काम किया जा रहा है। ऑटो एक्सपो 2025 में एमजी की ओर से Plug-in Hybrid तकनीक वाली कारों को शोकेस किया है। भारत के लिए इस तकनीक वाली कारों सबसे बेहतर हो सकती हैं। जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ ही बैटरी को भी दिया जाता है।

सवाल - JSW MG Select एक प्रीमियम डीलरशिप है। लेकिन किस तरह की कारों को इसके जरिए ऑफर किया जाएगा। क्या सिर्फ प्रीमियम कारें होंगी या फिर कम कीमत वाली कारों को भी इसके जरिए लाया जाएगा।

जवाब - JSW MG Select में सिर्फ खास कारों को ही ऑफर किया जाएगा। Select के जरिए उन कारों को ही ऑफर किया जाएगा जो काफी आकर्षक और हटकर होंगी। ऐसे में इनकी कीमत कम नहीं होगी लेकिन उनको अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक दाम पर लाया जाएगा।

सवाल - एक वाहन निर्माता के तौर पर आपको Budget 2025 से क्या उम्मीदें हैं।

जवाब - सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। अन्य कंपनियों भी EV में काफी बेहतरीन विकल्प ला रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर मुकाबला बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी काम किया जा रहा है। जिससे ईवी को बढ़ावा मिल पाएगा।

इस साल भारत में लॉन्च हो सकती हैं पांच सब फोर मीटर एसयूवी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

2025 भारत में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से कई एसयूवी को बाजार में पेश और लॉन्च किया जा रहा है। साल 2025 के दौरान किस कंपनी की ओर से कौन सी Sub 4 mtr SUV को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में एसयूवी सेगमेंट में जिन वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उनमें सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट सबसे ऊपर है। इस सेगमेंट में सभी निर्माताओं की ओर से अपने उत्पाद ऑफर किए जाते हैं। साल 2025 में सब फोर मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन सी पांच एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Syros होगी लॉन्च
किया की ओर से सिरसो को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में पेश किया गया है। लेकिन इसकी कीमतों की घोषणा जल्द की जाएगी। जिसके बाद इसे खरीदा जा सकेगा। कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया है। साथ ही इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प को भी दिया गया है। फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में इसके सभी छह वेरिएंट्स की कीमतों की घोषणा कर दी जाएगी।

Hyundai Venue New Generation

किया की तरह हुंडई भी सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में वेन्चु को ऑफर करती है। सेगमेंट में कई



नई एसयूवी आने के साथ ही अन्य कंपनियों की ओर से अपनी एसयूवी को अपडेट करने के कारण वेन्चु की नई जेनरेशन को लाना काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल कंपनी की ओर से वेन्चु की नई जेनरेशन को लाया जा सकता है। जिसमें एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

Tata Punch Facelift
टाटा की ओर से पंच एसयूवी को भी सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है।



रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके भी फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी कर रही है। जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान ही देखा जा चुका है। इसमें भी कई कॉस्मेटिक बदलावों को किया जा सकता है।

Maruti Fronx Hybrid
मारुति की ओर से इस सेगमेंट में फ्रॉन्क्स को ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की ओर से इस एसयूवी को हाइब्रिड तकनीक के साथ लाने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले इसे हाल में ही टेस्टिंग के दौरान

देखा गया है। इसके डिजाइन में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है लेकिन इसमें नए इंजन के साथ हाइब्रिड तकनीक को दिया जाएगा।

Mahindra XUV 3XO EV
महिंद्रा की ओर से इस सेगमेंट में XUV 3XO को ICE के साथ लाया जाता है। कंपनी ने इस गाड़ी को अप्रैल 2024 में ही लॉन्च किया था। जिसके बाद से इसको काफी पसंद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके Electric वर्जन को इस साल भारत में लॉन्च कर सकती है।

क्वालिटी, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक पर होंडा का फोकस, एक्टिवा ई और QC1 के लिए बनाई गई खास रणनीति

परिवहन विशेष न्यूज

एक्टिवा ई और क्यूसी। के लिए होंडा की रणनीति जापानी दो पहिया निर्माता Honda की ओर से जनवरी 2025 में Activa E और QC1 की कीमतों की घोषणा की गई है। दोनों स्कूटर्स को शुरुआत में चुनिंदा शहरों में उपलब्ध करवाया जाएगा। EV सेगमेंट के लिए HMSI की क्या रणनीति रहेगी। आने वाले महीनों में और किन वाहनों के EV वर्जन को लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का बाजार लगातार बढ़ा हो रहा है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से नए उत्पादों को लॉन्च किया जा रहा है। इसी क्रम में जापानी दो पहिया निर्माता Honda की ओर से भी Honda Activa E और QC1 को ऑटो एक्सपो 2025 में लॉन्च किया गया है। दोनों स्कूटर के लॉन्च के बाद कंपनी की रणनीति क्या होगी, इस पर Jagran.com ने होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर योगेश माथुर से खास बात की।

सवाल - होंडा की ओर से जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो के दौरान Honda Activa E और

QC1 की कीमतों की घोषणा की गई है। किस तरह से इनकी कीमतों को तय किया गया है। क्या अपने सेगमेंट के अन्य विकल्पों के मुकाबले इनकी कीमत ज्यादा नहीं है।

जवाब - किसी भी नए वाहन को बाजार में लॉन्च करते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब हमने यह तय किया कि हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपने नए स्कूटर्स को लाएंगे तो हमारा लक्ष्य यह था कि हम सभी तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फिक्सड बैटरी और स्विपेबल बैटरी वाले स्कूटर्स को लाए।

सवाल - आज के समय में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की क्वालिटी और रिसेल सबसे बड़ी चिंता है। ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर होंडा ने क्या काम किया है।
जवाब - जब हमने यूजर्स के सर्वे किए तो क्वालिटी सबसे बड़ी चिंता थी। साथ ही फिक्सड बैटरी वाले स्कूटर्स की कीमत तीन साल बाद काफी कम हो जाती है और खराबी आने पर बैटरी को बदलना भी महंगा होता है। इसके अलावा फिक्सड बैटरी वाले स्कूटर को चार्ज करने में भी पांच से छह घंटे तक का समय लगता है। इस दौरान चार्जिंग पर ध्यान भी देना पड़ता है जिससे हार्दसा न हो जाए। इन बातों का ध्यान में रखकर ही हमने ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन किया जो इन सभी चिंताओं को दूर करे।

सवाल - कई निर्माताओं की ओर से सिर्फ स्कूटर्स की बिक्री की जाती है। आपसे सेल्स और सर्विस पर ग्राहकों को परेशानी होती है। ऐसे में होंडा किस तरह से सेल्स के साथ ही सर्विस पर ग्राहकों की चिंता दूर करेगी।

जवाब - हमारी ओर से क्वालिटी, सर्विस सपोर्ट जैसे मार्कों के साथ ही आपसे सेल और सर्विस पर भी काफी काम किया गया है। मौजूदा समय में हमारे पास करीब 6500 टच पॉइंट्स हैं जिनको अलग अलग फेज में अपडेट किया जाएगा। इसके कारण ही हम QC1 को फिलहाल छह शहरों में ही ला रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं जिन शहरों में भी हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को उपलब्ध करवा रहे हैं वहां पर उनकी सर्विस और अन्य सपोर्ट को दिया जा सके, जिससे ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए सर्विस सेंटर पर अलग से मैनुअल को लाया गया है और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही वर्कशॉप में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया गया है। बैटरी और स्कूटर की उम्र को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। जिस तरह ICE स्कूटर्स की उम्र और रिसेल होती है उसी तरह हमने ईवी के लिए सर्विस पैकेज को भी घोषणा की है। जिसमें हम केयर और केयर प्लस पैकेज दे रहे हैं। केयर प्लस पैकेज पांच साल के लिए होगा और अभी तक कोई भी इस तरह के पैकेज को ऑफर नहीं कर रहा। नए सेगमेंट में स्कूटर लॉन्च करने से पहले ही हम इस तरह के पैकेज को इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने स्कूटर्स पर काफी ज्यादा भरोसा है।

सवाल - स्विपेबल बैटरी वाली तकनीक के साथ एक्टिवा को लाया गया है। स्कूटर चलाते हुए रेंज की चिंता कैसे दूर की जाएगी।
जवाब - एक्टिवा ई काफी यूनिवर्सल है। पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में एक्टिवा ई की बैटरी

को बदला जा सकता है, जिससे न तो ज्यादा समय खराब होगा और न ही रेंज की चिंता होगी। फुल चार्ज बैटरी से स्कूटर को 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और फिर एक मिनिट में बदलकर फिर से इतनी ही दूरी को तय किया जा सकेगा। बैटरी की उम्र की भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

सवाल - फिक्स और स्विपेबल बैटरी वाले स्कूटर को लाने का क्या मकसद था। किस तरह के ग्राहकों के लिए कौन सा स्कूटर सबसे बेहतर हो सकता है।

जवाब - युवाओं के साथ ही कम बजट वाले ग्राहकों के लिए हम QC1 को लेकर आए हैं। जिसमें 26 लीटर के करीब का बूट स्पेस भी मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रीमियम स्कूटर के अनुभव के लिए हमारी ओर से Honda Activa E को लाया गया है।
सवाल - Honda Activa E को स्विपेबल बैटरी के साथ लाया गया है और इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। होंडा की ओर से इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जवाब - होंडा एक्टिवा ई के लिए हमने शुरुआत में तीन शहरों को चुना है जिनमें बंगलुरु है। जिनमें एक अप्रैल 2025 से दिल्ली और मुंबई को भी शामिल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा लक्ष्य यह होगा कि हम हर पांच किलोमीटर में बैटरी स्टेशन को लगाएंगे। इस कारण हम अलग अलग फेज में इस स्कूटर को देश के अन्य शहरों में भी ऑफर करेंगे। फिलहाल बंगलुरु में 80 से ज्यादा स्टेशन लगाए जा चुके हैं। मुंबई और दिल्ली में भी बैटरी स्टेशन को लगाया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता पहले बैटरी स्टेशन लगाने की होगी और

उसके बाद ही हम अन्य शहरों में विस्तार करेंगे।

सवाल - बैटरी स्टेशन को शहरों में कहा लगाया जा रहा है। जिससे भविष्य में ग्राहकों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।

जवाब - होंडा की ओर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बंगलुरु में नन्मा मेट्रो जैसे पार्टनर के साथ टाई-अप किया है। इसके अलावा हमारे खुद के नेटवर्क पर भी हम बैटरी स्टेशन को लगा रहे हैं।

सवाल - क्या आपको लगता है कि होंडा की ओर से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर्स को देरी से लाया गया है। बाजार से आपको क्या उम्मीदें हैं।

जवाब - ग्लोबल स्तर पर हमारा लक्ष्य कार्बन न्यूट्रैलिटी पर है। हम यह नहीं सोचते कि हम लेट हो गए हैं, बल्कि हमारा सोचना है कि हम सही समय पर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आए हैं। बाजार में जब जिसकी जरूरत होती है हम तभी वहां एंटी करते हैं। इस समय हम अकेले ऐसे निर्माता हैं जिसके पास कई तरह के वाहन मौजूद हैं। हम पहले ऐसे निर्माता हैं जो फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक को बाजार में ऑफर कर रहे हैं। जब हमने ईवी की घोषणा की थी तब से हमारा लक्ष्य यह था कि हम सिर्फ फिक्सड बैटरी जैसी एक ही तकनीक की जगह स्विपेबल बैटरी जैसी तकनीक को भी ऑफर करेंगे। हमारा लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है और उत्पाद के महेदेनजर हम 2040 तक सभी को अपग्रेड कर कार्बन न्यूट्रैलिटी को हासिल करेंगे।

सवाल - होंडा के पोर्टफोलियो में फिलहाल दो स्कूटर को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लाया गया है। क्या भविष्य में कंपनी की ओर से और वाहनों को भी इस

सेगमेंट में लाया जा सकता है।

जवाब - सबसे पहले हमारी कोशिश यह है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Honda Activa E और Honda QC1 की स्थिति को बेहतर किया जाए। ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही हमारी लिए सबसे जरूरी है और उसके बाद कई और वाहनों को डेवलप किया जा रहा है जिनको बाद में लाया जाएगा।

सवाल - क्या भविष्य में फिक्सड बैटरी वाले वाहनों को लाया जाएगा या फिर स्विपेबल बैटरी वाले वाहनों को भी कंपनी की ओर से लाया जा सकता है।
जवाब - हमारे पास दोनों तरह की तकनीक मौजूद है, जिनको Honda Activa E और QC1 में लाया गया है। ऐसे में भविष्य में उसी तकनीक के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे ग्राहकों की ओर से ज्यादा पसंद किया जाएगा।

सवाल - क्या इस साल और उत्पादों को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है।
जवाब - सबसे पहली कोशिश मौजूदा दोनों उत्पादों को ही स्टेबल करेंगे। जिसके बाद अन्य वाहनों को बाजार में लाया जाएगा।

सवाल - एक्टिवा होंडा का सबसे बेहतरीन ब्रॉन्ड है। 2001 से ही इसे भारत में काफी पसंद किया गया है। फिलहाल हमारे पास दोनों तरह की तकनीक हैं। अगर भविष्य में ऐसे कोई जरूरत लगती है कि एक्टिवा को स्विपेबल के साथ फिक्सड बैटरी के साथ लाया जाए तो ऐसा किया जा सकता है।

नीति आयोग और नैसकॉम फाउंडेशन ने मिलकर एक लाख लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की शुरुआत की

परिवहन विशेष न्यूज

पहले चरण में नैसकॉम फाउंडेशन 60 विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी ब्लॉक्स को डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने पर फोकस करेगा। इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे सभी 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करने पर आधारित यह पहल अंतिम मील तक खासकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत, नीति आयोग के साथ साझेदारी में, नैसकॉम फाउंडेशन ने भारत के आकांक्षी ब्लॉक्स में एक लाख लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य साधा है। इस पहल के पहले चरण में विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के 60 ब्लॉक्स में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण और आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसके बाद, इस कार्यक्रम को सभी अन्य आकांक्षी ब्लॉक्स तक बढ़ाया जाएगा। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हुए, यह पहल सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जो न सिर्फ समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि भारत की डिजिटल यात्रा में कोई भी पीछे न रहे।

नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा आयोजित लॉन्च



इवेंट में श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग; अन्य नीति आयोग सदस्य; डॉ. ओ.पी. अग्रवाल, प्रतिष्ठित साथी; श्री आनंद शेखर, अतिरिक्त मिशन निदेशक, आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम; ज्योति शर्मा, सीईओ, नैसकॉम फाउंडेशन; आदित्य मिश्रा, प्रमुख, डिजिटल साक्षरता,

नैसकॉम फाउंडेशन; तथा डॉ. महेंद्र कुमार, अतिरिक्त मिशन निदेशक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम की उपस्थिति दर्ज की गई। इवेंट ने सरकार के इस प्रयास को उजागर किया, जो अंतिम छोर तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल इस बात पर जोर

देती है कि तकनीकी का उपयोग समावेशी विकास और समान अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए, अब इस पहल का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले 55

आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन अब इसे ब्लॉक्स तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाने और उन्हें जरूरी संसाधन प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, पीवीटीजी समुदायों में साक्षरता दर सिर्फ 47.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इस डिजिटल असमानता को खत्म करने के लिए नैसकॉम फाउंडेशन ने यह पहल शुरू की है, ताकि इन समुदायों में समग्र विकास और समावेशन को बढ़ावा मिल सके।

नैसकॉम फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज्योति शर्मा ने कहा, 'रूपरेखा की आज की दुनिया में प्रगति और सशक्तिकरण की मुख्य शक्ति है। इस विकास को हासिल करने के लिए डिजिटल साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि भारत के सबसे दूरदराज इलाकों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले पीवीटीजी (विशेष रूप से संरक्षित जनजातीय समूहों), के पास सतत विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति हो। आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम, जो नीति आयोग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, सिर्फ डिजिटल अंतर को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में हर किसी की सक्रिय भागीदारी

सुनिश्चित करने के बारे में है।'

यह प्रशिक्षण बेसिक कम्प्यूटर कौशल, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के प्रभावी उपयोग को कवर करता है, जिससे प्रतिभागी आत्मविश्वास के साथ डिजिटल दुनिया में मार्गदर्शन कर सकते हैं। समुदाय तक पहुंच स्थापित करने वाले अभियानों का भी इस पहल में महत्वपूर्ण योगदान है, जो डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए, स्थानीय समुदाय के चैंपियंस को मास्टर ट्रेनर्स और डिजिटल एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो संबंधित ब्लॉक प्रशासन के समर्थन से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और समुदाय को गतिशील बनाते हैं।

इस साझेदारी के माध्यम से, नैसकॉम फाउंडेशन प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के प्रमुख संकेतकों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना, सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए जागरूकता बढ़ाना, और डिजिटल साक्षरता पर सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल साक्षरता और इसकी पहुंच के बीच जो अंतर है, उसे खत्म करके, आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम डिजिटल रूप से अधिक सशक्त भारत की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

सेबी को मिलेगा नया चीफ, सरकार ने मंगाया आवेदन; सैलरी-योग्यता समेत जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

मौजूदा सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। सरकार वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिश पर सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। समिति योग्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की भी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है जिसने पद के लिए आवेदन नहीं किया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) का कार्यकाल पूरा होने वाला है। सरकार ने उनकी जगह नए चेयरपर्सन के लिए आवेदन मंगाया है। मौजूदा चेयरपर्सन बुच का तीन साल का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। बुच ने 2 मार्च, 2022 को पदभार संभाला था।

वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में 17 फरवरी तक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा, 'रिनयुक्त कार्यभार संभालने की तारीख से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए या नियुक्त

व्यक्ति को उम्र 65 साल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

कितना होगा वेतन
सरकारी विज्ञापन के मुताबिक, सेबी चेयरपर्सन को भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतन मिलेगा। यह फिलहाल 5,62,500 रुपये महीना है। इसमें घर और गाड़ी की सुविधा शामिल नहीं है। वित्त मंत्रालय का यह भी कहना है कि रेगुलेटर के तौर पर सेबी की भूमिका काफी अहम है। ऐसे में चेयरपर्सन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ पैमानों पर खरा उतरना होगा।

विज्ञापन के मुताबिक, 'उम्मीदवार निष्ठावान और प्रतिष्ठित शख्स होना चाहिए। उसकी 25 साल से अधिक और 50 साल से कम होने चाहिए। उम्मीदवार के पास सिस्को/रिटेल मार्केट से संबंधित समस्याओं से निपटने में दिखाई गई क्षमता, या कानून, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र का विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी होगा।'

हितों का टकराव न हो
साथ ही विज्ञापन में कहा गया है, 'सेबी चेयरपर्सन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास ऐसे कोई

वित्तीय या अन्य हित न हों और न ही आगे होंगे, जो चेयरपर्सन के रूप में उसके कामकाज को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सकें।'

सरकार वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिश पर सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। समिति योग्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की भी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है, जिसने पद के लिए आवेदन नहीं किया है।

कैसा रहा माधवी पुरी बुच का कार्यकाल
सेबी चीफ के तौर पर माधवी पुरी बुच का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर आरोप लगाया था कि अदाणी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। इसमें अदाणी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप था।

हालांकि, सेबी चीफ और उनके पति ने आरोपों को खारिज कर दिया था। सेबी चीफ के तौर पर माधवी पुरी बुच ने प्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में रिटेल इन्वेस्टर्स को भागीदारी रोकने के लिए नियमों को काफी सख्त किया। इसे भी मार्केट के कैश फ्लो पर नकारात्मक असर डालने वाला फैसला बताया गया।



नेहरू से मनमोहन सिंह तक... पांच प्रधानमंत्री, जिन्होंने बजट भी पेश किया

परिवहन विशेष न्यूज

बजट 2025 देश की आर्थिक दशा और दिशा तय करने में बजट अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अक्सर किसी तज्जुबकार नेता को दी जाती है। लेकिन भारतीय इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब खुद प्रधानमंत्री को बजट पेश करना पड़ा। इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हो गई थी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बजट सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की आर्थिक दिशा को काफी हद तक स्पष्ट करेगा। अगर बजट की बात करें, तो इसने देश की आर्थिक दिशा और दशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। इसने कई ऐतिहासिक पल भी देखे हैं। जैसे कि बजट को ऐसे लोगों ने भी पेश किया है, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे या फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। आइए ऐसी शख्सियतों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1958 में केंद्रीय बजट पेश किया। इसकी वजह भी काफी दिलचस्प



थी। दरअसल, उस वक्त वित्त मंत्री टी टी कृष्णामाचारी थे। लेकिन, बजट से ठीक पहले मुद्रा घोटाला उजागर हुआ। उसमें कृष्णामाचारी का नाम भी शामिल था। इस घोटाले चलते वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह नेहरू ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और खुद बजट पेश किया।

मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई के नाम भारत में सबसे ज्यादा केंद्रीय

बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वह जनता पार्टी के साथ 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई ने 8 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट समेत कुल 10 बजट पेश किए। वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1959 से 1963 तक लगातार बजट पेश किए। साथ ही 1962 का अंतरिम बजट भी पेश किया। उन्होंने 1967 के अंतरिम बजट के साथ-साथ 1967, 1968 और 1969 के बजट भी पेश किए।

इंदिरा गांधी

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी ने 1969 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1970 का केंद्रीय बजट पेश किया। एक साल बाद उन्होंने गृह मंत्री यशवंतराव चव्हाण को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया।

राजीव गांधी

इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। इसकी नौबत तत्कालीन वित्त मंत्री वी पी सिंह को उनके पद से हटाने के बाद आई। राजीव गांधी ने जनवरी और जुलाई 1987 के बीच कुछ समय के लिए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था।

मनमोहन सिंह

मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक पी वी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1991 में बजट पेश किया, जिसे देश के इतिहास में सबसे क्रान्तिकारी बजट माना जाता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए उदारकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की वकालत की गई थी। 2004 में कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए की सरकार बनने के बाद वह प्रधानमंत्री भी बने।

कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर, कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?



वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश फिटमेंट फैक्टर के आधार पर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले साल यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होगा। नए वेतन आयोग के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी भारी इजाफे की उम्मीद है। यह सब फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है।

कैसे बढ़ेगी सैलरी

वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश फिटमेंट फैक्टर के आधार पर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे चीजों पर गौर करते तय किया जाता है।

महंगाई दर: वेतन आयोग यह जानने की कोशिश करता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है और उसका कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या पड़ा है। जैसे कि उनके लिए घर और गाड़ी खरीदना कितना मुश्किल हुआ है।

इन खर्चों पर फोकस: वेतन आयोग की नई सैलरी की सिफारिश करते समय चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादी जैसे खर्चों को ध्यान में रखेगा।

इकोनॉमी की स्थिति: वेतन आयोग देश की वित्तीय स्थिति पर भी गौर करता है। अगर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी रहती है, तो वेतन में ज्यादा वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है।

कर्मचारियों का प्रदर्शन: वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है। अगर कर्मचारियों का ओवरऑल परफॉर्मंस बेहतर रहता है, तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है।

बाजार पर भी नजर: वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते वक्त यह भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियों अपने कर्मचारियों को कितना हाइक दे रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन तय करने में आसानी होती है।

कितनी बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी
फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है। इसमें थते और परफॉर्मंस पे भी शामिल होगा। पेंशनयोगियों को भी उसी अनुपात में फायदा मिलेगा।

7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे तय हुई थी?

6वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये महीना था। इसे 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 रुपये महीना कर दिया गया था। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना अधिक थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.2 फीसदी का उछाल आया था।

आसान हो सकता है घर खरीदना, पीएम किसान योजना का पैसा भी बढ़ने की उम्मीद

सस्ते मकान की बिक्री लगातार कम हो रही है। सब्सिडी की योग्यता सीमा में बढ़ोतरी के साथ होम लोन के ब्याज पर टैक्स सब्सिडी की सीमा को बढ़ाने से रियल एस्टेट सेक्टर को चुनौतियों से राहत मिलेगी। बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को भी राहत दी जा सकती है। पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना छह हजार रुपये सरकार की तरफ दिए जाते हैं।

नई दिल्ली। सस्ते मकान की खरीदारी को सरकार बजट में प्रोत्साहित कर सकती है। अभी सरकार 35 लाख तक के मूल्य के मकान की खरीदारी को लेकर लिए जाने वाले लोन को ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में 35 लाख तक की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक किया जा सकता है। इससे सस्ते मकान की बिक्री बढ़ सकती है और निर्माण सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा।

आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार निर्माण सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का फैसला ले सकती है। सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार का सृजन निर्माण सेक्टर में होता है। लेकिन गत



चार तिमाही से निर्माण सेक्टर की बढ़ोतरी दर कम हो रही है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में निर्माण सेक्टर में 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही जबकि पहली तिमाही में यह बढ़ोतरी 10.5 प्रतिशत तो पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में यह बढ़ोतरी दर 13.6

प्रतिशत की थी। उससे पहले की तिमाही में निर्माण सेक्टर में 8.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।

जानकारों का कहना है कि सस्ते मकान की बिक्री लगातार कम हो रही है। हाउसिंगडॉटकॉम और प्रोपर्टाइमरडॉटकॉम के सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने बताया

कि सब्सिडी की योग्यता सीमा में बढ़ोतरी के साथ होम लोन के ब्याज पर टैक्स सब्सिडी की सीमा को बढ़ाने से रियल एस्टेट सेक्टर को चुनौतियों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से टैक्स में छूट के लिए दो लाख तक के ब्याज को सीमा चला आ रही है। इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत होम लोन धारक इनकम टैक्स में छूट के लिए अधिकतम अपनी आय में दो लाख तक का ब्याज का फायदा ले सकते हैं।

पीएम किसान के लिए तहत मिल सकती है राहत
पीएम किसान के लिए तहत मिल सकती है राहत बजट में पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को भी राहत दी जा सकती है। पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना छह हजार रुपए सरकार की तरफ दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण खपत को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है।

सूत्रों का कहना है कि पीएम किसान की राशि में एक हजार रुपए का इजाफा किया जा सकता है। इससे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। जानकारों का कहना है कि आगामी बजट में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खपत बढ़ाने की है क्योंकि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होती दिख रही है।

